तिब्बत देश

चीनी उपनिवेशवाद बनाम तिब्बती लोकतंत्र

तिब्बती शरणार्थी समाज इन दिनों अपनी निर्वासन सरकार के कालोन ट्रीपा (प्रधानमंत्री) और नई संसद के चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ है। यह तीसरा मौका होगा जब निर्वासन में रहने वाला तिब्बती समाज सीधे मतदान से अपने लिए कालोन ट्रीपा का चुनाव करेगा। एक साथ किए जाने वाले इस चुनाव में 15वीं संसद को भी चुना जाएगा। पूरी दुनिया में निर्वासन में रहने वाले सैंकड़ों शरणार्थी समाजों में से केवल तिब्बती समाज ऐसा है जो लोकतांत्रिक और गुप्त मतदान के माध्यम से अपनी 'निर्वासन सरकार' का चुनाव करता है।

10 जून को तिब्बती सरकार के निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि 18 अगस्त तक सभी वोटरों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद वे 3 अक्तूबर को प्रधानमंत्री और संसद के लिए उम्मीदवार तय करने वाले आरंभिक दौर के चुनाव में वोट डाल सकेंगे। चुनाव का निर्णायक दौर 20 मार्च 2011 के दिन होगा और इस चुनाव में जीतने वाला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अगस्त 2011 में वर्तमान प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त होने पर अपना पद संभालेगा। उसी अवसर पर तिब्बत की 15वीं संसद भी अपना कार्यभार संभालेगी।

दुनिया भर की राजनीति पर नजर रखने वालों के लिए यह चुनाव यकीनन कौतुहल भरा होगा। उनमें से कई लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले 51 साल से अपने देश से बाहर रहने को मजबूर तिब्बती शरणार्थी समाज की धर्मशाला में अपनी 'सरकार' और संसद है बल्कि वह एक निष्पक्ष 'चुनाव आयोग' की देखरेख में गुप्त मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी करता है। शायद यही कारण है कि लोकतांत्रिक आधार पर संगठित यह समाज चीन जैसी बाहुबली व्यवस्था के खिलाफ पिछले पांच दशक से मजबूती से टिका हुआ है और तिब्बत की मुक्ति के लिए उसे पूरे दमखम के साथ टक्कर दे रहा है। तिब्बती समाज की इस सफलता का श्रेय काफी हद तक इस समाज के नेता दलाई लामा की दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता को जाता है।

1951 में तिब्बत पर चीन के जबरन कब्जे और 1959 में चीनी उपनिवेशवाद के खिलाफ तिब्बती जनक्रांति के विफल होने के बाद दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तब उनके साथ लगभग 80 हजार तिब्बती नागरिक भी भागकर भारत आ गए थे। निर्वासन में आने के बाद दलाई लामा ने जिन मुख्य बातों पर अपना ध्यान केंद्रित किया वे थीं तिब्बती संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखने के प्रयास करना, शरणार्थी समाज को आधुनिक शिक्षा दिलाना और भविष्य के तिब्बत के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना। उन्होंने निर्वासन में आने के एक साल के भीतर ही भविष्य के तिब्बत के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया।

इससे पहले तिब्बत में कई सदियों से एक धर्म आधारित शासन व्यवस्था चली आ रही थी जिसमें सारे अधिकार देश के सबसे बड़े धार्मिक गुरू और शासक दलाई लामा के हाथ में थे। नए संविधान में एक निर्वाचित संसद और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली व्यवस्था रखी गई। आरंभिक दौर में सांसदों और मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार दलाई लामा के ही हाथ में था। लेकिन बाद के वर्षों में दलाई लामा की व्यक्तिगत पहल पर संविधान को अधिक से अधिक लोकतांत्रिक बनाने वाले नियम जुड़ते गए। तिब्बती संविधान के लोकतंत्रीकरण की यह परंपरा अब जिस मुकाम तक पहुंच चुकी है वहां न केवल सांसदों और प्रधानमंत्री का चुनाव हर पांच साल बाद गुप्त वयस्क मताधिकार के माध्यम से तिब्बती शरणार्थी समाज करता है बल्कि निर्वाचित संसद को यह संवैधानिक अधिकार भी मिल चुका है कि वह दलाई लामा के काम से असंतुष्ट होने पर उसे राष्ट्राध्यक्ष के पद से हटा भी सकती है। एक ऐसे युग में जहां दुनिया भर के लोकतांत्रिक शासक किसी न किसी बहाने अधिक से अधिक अधिकार अपने हाथ में रखने में जुटे हुए हों वहां दलाई लामा द्वारा अपनी संसद को इस तरह का अधिकार देना लोकतंत्र में उनकी आस्था का स्तर दर्शाता है।

हालांकि तिब्बत की निर्वासन सरकार ने काफी हद तक भारतीय चुनाव प्रणाली को अपनाया है जिसमें गुप्त वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। लेकिन इसमें कई नए तत्व भी हैं। उदाहरण के लिए इसमें प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव की प्रणाली शामिल की गई है। चुनाव के पहले दौर में हर मतदाता एक सादे कागज़ पर अपनी पसंद के उम्मीदवार का नाम सुझाता है। इस मतदान के आधार पर उन उम्मीदवारों के नामों को शार्टलिस्ट किया जाता है जिन्हें 25 से ज्यादा मतदाताओं का समर्थन मिला हो। बाद में इस सूची में से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के बीच चुनाव होता है। कुल मतदान के 51 प्रतिशत वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। लेकिन अगर किसी भी उम्मीदवार को इतने वोट न मिलें तो पहले दो उम्मीदवारों के बीच फिर से मतदान कराया जाता है। इससे पहले अंतिम चुनाव में कम से कम दो उम्मीदवारों का होना जरूरी था लेकिन इस बार तिब्बती संसद ने इस शर्त को समाप्त कर दिया है। दुनिया भर में फैले लगभग डेढ़ लाख तिब्बतियों में से 1 लाख 20 हजार वयस्क हैं।

2001 और 2006 के पहले दो चुनावों में प्रो. सामदोंग रिंपोछे भारी बहुमत से जीत चुके हैं। लेकिन संविधान में किसी एक व्यक्ति के लिए लगातार केवल दो बार प्रधानमंत्री बनने की सीमा को देखते हुए इस बार तिब्बती सरकार की सबसे ऊंची कुर्सी पर एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। इस बार के चुनाव अभियान में कई ऐसी नई बातें हैं जो तिब्बती लोकतंत्र के और पकने का संकेत देती हैं। उदाहरण के लिए पिछले चुनाव में मतदाताओं की भारी उदासीनता को ध्यान में रखते हुए (मतदान केवल 26.8 प्रश) इस बार तिब्बती महिला संगठन टीडब्लूए समेत कई संगठनों और प्रबुद्ध नागरिकों ने मतदान से साल भर पहले ही एक जनजागरण अभियान चलाया है जिसका लक्ष्य आम मतदाता को मुद्दों को समझने, रजिस्ट्रेशन करवाने और मतदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। तिब्बत के इतिहास में यह पहला मौका है जब आम जनता तब अपनी बात पहुंचाने के लिए इंटरनेट चुनाव मैदान का रूप ले चुका है। कुछ उम्मीदवारों के समर्थकों ने विशेष वेबसाइटें लांच की हैं। प्रमुख उम्मीदवारों के बीच सार्वजनिक बहस के लिए सभाओं के आयोजन हो रहे हैं और इंटरनेट, प्रकाशनों तथा दूसरे सार्वजनिक मंचों पर आम मतदाता अपनी राय खुलकर प्रकट कर रहे हैं। इस चुनाव अभियान का एक आशावादी पक्ष यह है कि पिछले कई चुनावों के दौरान चुनावी बहस और मतदान के प्रति उपेक्षा रखने वाला युवा समाज भी इस बार काफी सक्रिय दिख रहा है।

लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस लोकतांत्रिक अभियान ने तिब्बत पर कब्जा जमाए बैठी चीन सरकार की भविष्य की योजनाओं में पलीता लगा दिया है। पिछले कई साल से चीनी नेता उस दिन के लिए योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं जब 75 वर्षीय वर्तमान दलाई लामा परलोक सिधारेंगे और उन्हें दलाई लामा के एक कठपुतली अवतार को तिब्बत पर थोपने का मौका मिलेगा। लेकिन तिब्बती जनता द्वारा चुने गए शासनाध्यक्ष और संसद के सामने चीन सरकार की कठपुतली टिकी रह पाएगी इस पर पूरी दुनिया को शक है। असल में वर्तमान दलाई लामा ने तिब्बती शासन व्यवस्था में लोकतंत्र का जो बीज 1960 में बोया था वह अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। अपनी जनता को लोकतंत्र के राजमार्ग पर डालकर दलाई लामा ने न केवल उसे अनंतकाल तक चीनी उपनिवेशवाद से टक्कर लेने का हौसला और संस्कार दिया है बल्कि विश्व मंच पर तिब्बत के सवाल को तब तक जिंदा रखने की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दी है जब तक चीनी उपनिवेशवाद भी अन्य उपनिवेशवादियों की तरह इतिहास के कूड़ेदान को समर्पित नहीं हो जाता।

— विजय क्रान्ति

चीन सरकार ने खराब स्वास्थ्य के कारण तिब्बती लेखक को रिहा किया

ड्रुक्लो (शोकजंग)

काउंटी के जन सुरक्षा ब्यूरो (पीएसबी) ने 2008 और 2009 के मामले की छानबीन करने के बाद इन भिक्षुओं को पूछताछ करने के लिए काउंटी पीएसबी के मुख्यालय में बुलाया था। पूछताछ करने के बाद 32 साल के केलसांग धारगे, 22 साल के ताशी लुंडुप, और 35 साल के ताशी वांगडू को 7 जून को गिरफ्तार कर लिया गया।

(फायुल डॉट कॉम, गांतोक, 2 जून) चीन सरकार ने एक तिब्बती छात्र को करीब 30 दिनों तक हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया है। दक्षिण भारत के सेरा मठ के एक लामा शिंगसा रिंपोछे के मुताबिक चीन सरकार ने युनिवर्सिटी ऑफ लॉन्झॉ के छात्र को 8 मई को मुक्त किया। इस छात्र की शारीरिक हालत बहुत नाजुक है। शिंगसा रिंपोछे को अपने सूत्रों से पता चला है कि ड्रुक्लो, जो शोकजंग नाम से लेख वगैरह लिखते हैं, से लगातार घंटों तक पूछताछ की जाती रही और वह ठीक तरह से सो नहीं पाया है। शिंगसा रिंपोछे ने कहा कि मैंने सुना है कि शोकजंग का स्वास्थ्य बहुत खराब है और वह अभी कुछ लिख पाने की हालत में नहीं है। पूछताछ के दौरान उससे जबर्दस्ती यह कबूल कराया गया कि उसका तिब्बती युवा कांग्रेस से संबंध है, जिसे चीनी सरकार निवार्सित तिब्बतियों का एक आतंकवादी संगठन मानती है। उस पर शिंगसा रिंपोछे से संबंध रखने का भी आरोप लगाया गया। शिंगसा रिंपोछे ने तिब्बत सीमा से बाहर तिब्बत की आजादी के लिए कई राजनीतिक अभियानों का संचालन किया है और वे एक वेबसाइट www.wokar.net भी चला रहे हैं, जिसमें तिब्बत में रहने वाले लोग लिखा करते हैं। शिंगसा रिंपोछे के मुताबिक शोकजंग ने दोनों ही आरोपों को मानने से इनकार कर दिया है। शिंगसा रिंपोछे ने कहा है कि मेरा वेबसाइट तिब्बत में रहने वाले लोगों का आलेख छापता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत आरोप है कि शोकजंग का मुझसे कोई संबंध है। ड्रुक्लो को ताशी रबतेन (लेखकीय नाम – से उरंग) के साथ 6 अप्रैल 2010 को गिरफ्तार किया गया था।

चामदो के जोमदा काउंटी में 3 बौद्ध भिक्षु गिरफ्तार

(फायुल.कॉम, धर्मशाला, जून 12)

चीन सरकार ने तिब्बत के तीन बौद्ध भिक्षुओं को गिरफ्तार किया है। वॉयस ऑफ टिबेट रेडियो ने एक रिपोर्ट में बताया कि तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में चामदो के जोमदा काउंटी के थांगपू टाउनशिप में स्थित वारा मठ से चीन सरकार ने तीन बौद्ध भिक्षुओं को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी 7 जून 2010 को हुई है। इन भिक्षुओं पर जोमदा काउंटी में 2008 और 2009 में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने और इसमें शामिल होने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। काउंटी के जन सुरक्षा ब्यूरो (पीएसबी) ने 2008 और 2009 के मामले की छानबीन करने के बाद इन भिक्षुओं को पूछताछ करने के लिए काउंटी पीएसबी के मुख्यालय में बुलाया था। पूछताछ करने के बाद 32 साल के केलसांग धारगे, 22 साल के ताशी लुंडुप, और 35 साल के ताशी वांगडू को 7 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले महीने चीन सरकार ने इसी मठ के छह अन्य भिक्षुओं को भी गिरफ्तार कर लिया था। 25 साल के थिनले, 27 साल के नांगसे, सोगोन और केलसंग को 15 मई को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 40 साल के सोनम गोनपो और 29 साल के ताग्याल को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। मार्च में भी 2 भिक्षुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर 10 मार्च 2010 को तिब्बती राष्ट्रीय क्रांति दिवस के 51वें सालगिरह के मौके पर सरकारी वाहनों में आग लगाने का आरोप है।

3 अप्रैल 2008 को भी जोमदा काउंटी के वारा मठ के भिक्षुओं ने चीनी अधिकारियों के द्वारा थोपी जा रही "देशभक्तिपूर्ण शिक्षा" का विरोध किया था। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से साफ कहा था कि वे अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने धार्मिक नेता दलाई लामा का साथ नहीं छोड़ेंगे।

ह्यूमन राइट्स वाच ने चीन सरकार से की तिब्बती पर्यावरण कार्यकर्ता को छोड़ने की अपील

(दि गॉर्जियन, 11 जून, 2010)

मानवारधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वाच ने चीनी सरकार से उन तीन पर्यावरण कार्यकर्ताओं को छोड़ने की अपील की है, जिन्होंने दुनिया की छत यानी तिब्बत के पठार के पारिस्थितिकी को बचाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। सबसे हाल में करमा समुद्रुप को हिरासत में लिया गया है। करमा समुद्रुप अमीर तिब्बती कला संग्रहक हैं। उन्होंने थ्री रिवर्स एनवॉयरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना की है और यांग्जे, येलो और मेकांग नदियों के जल स्रोत क्षेत्र के संरक्षण के लिए अभियान चलाया। उनके समूह ने कई पुरस्कार हासिल किए हैं, जिसमें अर्थ प्राइज भी शामिल है, जो अर्थ हांग कांग और फोर्ड मोटर कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है।

उन्हें इस साल के आरंभ में कब्र को खोदने और सांस्कृतिक कलाकृतियों को चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि खबर है कि 12 साल पहले पुलिस ने उन पर लगे इन आरोपों को खारिज कर दिया था।

उनकी सुनवाई 1 जून को होने वाली थी, लेकिन इस आरोप के साथ सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया गया कि अपने अन्य दो भाइयों को छुड़ाने के लिए वे आक्रामक लॉबिंग कर रहे हैं। उनके दो भाइयों रिंचेन समुद्रुप और जिग्मे नामग्याल को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार कर लिया गया था, जब उनके अलग पर्यावरण संगठनों वॉलेंटरी एनवॉयरमेंटल प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ खाम आंचुंग सेंगनामजोंग ने स्थानीय अधिकारियों के द्वारा लुप्त होते जा रहे जानवरों के शिकार की बात का खुलासा कर दिया था।

जिग्मे नामग्याल को राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचान के लिए 21 महीने की दोबारा शिक्षा देने के साथ ही सश्रम कारावास की सजा दी जा रही है। अधिकारियों ने उनपर पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और धार्मिक ग्रंथों के अवैध तरीके से संग्रह करने, याचिका दायर करने, दलाई लामा के समर्थकों को प्रचार सामग्री देने का आरोप लगाया है। उधर रिंचेन समुद्रुप को बिना सुनवाई के ही हिरासत में रखा गया है।

ह्यूमेन राइट्स वाच के एशिया एडवोकेसी डायरेक्टर सोफी रिचर्डसन ने कहा कि इससे चीनी सरकार के चरित्र का पता चलता है। गिरफ्तार किए गए लोग वो लोग हैं, जिनकी स्थिति तिब्बत के प्रति चीनी सरकार की नीतियों–आर्थिक रूप से सफल, सिर्फ कुछ सरकारी मान्यताप्राप्त संस्कृतियों और पर्यावरणीय मुद्दों को प्रोत्साहन –से बिल्कुल मेल खाते हैं, फिर भी वे अपराधी की तरह से देखे जा रहे हैं। प्रदूषण पर काम करने वाले एक अन्य कार्यकर्ता वू लिहोंग के साथ भी चीनी सरकार ने ऐसा ही व्यवहार किया। तीन साल के कारावास की सजा पूरी कर हाल ही में निकलने के बाद उन्होंने बताया कि कारावास में सुरक्षा गार्डों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा।

उन्होंने गार्जियन को बताया कि जाई लेक्सिन नाम के एक सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें बेंत से पीटा और जलती सिगरेट से जलाया, एक अन्य अधिकारी वांग केवी ने उनका सिर दीवार पर दे मारा, जबकि एक अन्य अधिकारी जिनका उपनाम शेन है, ने उनसे जबरदस्ती कबूल करवाने के लिए पीटा।

वू को 2005 में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने पर्यावरण योद्धा का खिताब दिया था। उन्हें यह खिताब जियांगसू प्रांत में ताई झील को साफ करवाने में उनके योगदान के लिए दिया गया था। बाद में ब्लैकमेल के आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया गया। हालांकि चीनी में सिविल सोसाइटी पर सरकार का कड़ा नियंत्रण है, फिर भी केंद्र सरकार पर्यावरण के लिए काम करने वाले एनजीओ को पर्यावरण संबंधी नियमों को तोड़ने वाले स्थानीय अधिकारियों का नाम सामने लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन केंद्र सरकार की पहुंच सीमित है और स्थानीय अधिकारी आराम से एनजीओ पर यह आरोप मढ़ सकते हैं कि कोई एनजीओ देश विरोधी काम कर रहा है।

जब गार्जियन ने पर्यावरण सुरक्षा के डिप्टी मिनिस्टर से इस बारे में शिकायत की तो उन्होंने किसी एक मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार पर्यावरण पर काम करने वाले एनजीओ को प्रोत्साहित करती है। जब तक वे कानून का पालन करते हैं, तब तक सरकार के हर स्तर से उन्हें सहयोग मिलता है।

ह्यूमेन राइट्स वाच के एशिया एडवोकेसी डायरेक्टर सोफी रिचर्डसन ने कहा कि इससे चीनी सरकार के चरित्र का पता चलता है। गिरफ्तार किए गए लोग वो लोग हैं, जिनकी स्थिति तिब्बत के प्रति चीनी सरकार की नीतियों–आर्थिक रूप से सफल, सिर्फ कुछ सरकारी मान्यताप्राप्त संस्कृतियों और पर्यावरणीय मुद्दों को प्रोत्साहन –से बिल्कुल मेल खाते हैं, फिर भी वे अपराधी की तरह से देखे जा रहे हैं।

मजदूरों के हड़तालों के मद्देनजर चीन ने स्ट्राइक हार्ड अभियान शुरू किया

(ईपोच टाइम्स, 30 जून, 2010)

पिछले कुछ समय से चीन में मजजूरों की ओर से किए जा रहे हड़तालों से चीन में मजदूरों के अधिकारों की वास्तविक स्थिति और चीनी समाज में फैली असमानता का पता चलता है। इससे देखते हुए चीन सरकार ने ''स्ट्राइक हार्ड'' अभियान शुरू किया है।

रपोर्ट में कहा गया है कि इन विदेशी कंपनियों में हड़ताल की इजाजत देने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार की छवि में सुधार होगा। दुनिया को लगेगा कि चीन में आम आदमी के मौलिक अधिकारों का अब दमन नहीं हो रहा है। पिछले मई में जिन सात कंपनियों में हड़ताल हुए, उसमें से दो मामले को उदाहरण के तौर पर पेश किया जा सकता है।

विश्लेषकों के मुताबिक चीनी समाज में व्याप्त असमानताओं, अन्याय और निरंतर बढ़ रही महंगाई के कारण मजूदरों के ये हड़ताल देखे जा रहे हैं। मजूदर ना सिर्फ वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, बल्कि स्वतंत्र यूनियन बनाने की भी अनुमति मांग रहे हैं।

अगर ये हड़ताल यूं ही जारी रहे तो दुनिया की फैक्टरी के रूप बनी चीन की पहचान को नुकसान पहुंच सकता है और साम्यवाद की लोकप्रियता में भी कमी आ सकती है। इन हड़तालों का कड़ाई से दमन भी करना चीन के हित में नहीं है। बहरहाल लोक सुरक्षा से संबंधित चीनी मंत्रालय ने 13 जून को घोषणा की कि वह 7 महीनों तक चलने वाला एक स्ट्राइक हार्ड कैंपेन शुरू करने जा रहा है। इसके माध्यम से वह चीनी समाज में फैलती जा रही हिंसा का कड़ाई से दमन करेगी, क्योंकि तेजी से बदल रहे चीनी समाज में इन हिंसाओं से असुरक्षा बढ़ती जा रही है।

<u>चीनी मजदूरों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैल रही है</u>

जिलिन प्रांत में विस्थापित मजदूरों के अधिकारों पर काम करने वाले कार्यकर्ता जू यिमिन ने स्वतंत्र मजदूर यूनियन की मांग की है। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है कि फॉक्सकॉन में अत्महत्याओं की देखी जा रही घटनाओं और देश भर में मजदूरों के हड़तालों से साफ है कि चीन में मजदूरों के पास ना तो कोई अधिकार हैं, ना ही उनकी कोई आवाज है।

न्यू तांग डायनेस्टी टेलीविजन यानी एनटीडीटीवी ने 24 जून को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले साल उत्तरपूर्वी जिलिन प्रांत से पलायन करने वाले मजदूरों ने स्वतंत्र मजदूर यूनियन बनाने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दी गई।

ठीक इसी वक्त सरकारी ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने एक बयान जारी कर कहा कि चीन में पलायन करने वाले नौजवान मजदूर अपनी अलग मांग सरकार के पास रख रहे हैं। उनकी ये गतिविधियां देश की अखंडता और विकास के लिए खतरा हैं।

<u>चीन में अधिकारियों का संघ हडतालों का करता है दमन</u>

चीन में श्रमिक संगठन सरकार के अधीन काम करते हैं और अधिकतर मामलों में प्रबंधन और स्थानीय कम्युनिस्ट नेताओं का पक्ष लेते हैं। वे मजदूरों की आवाज नहीं उठाते हैं। दि इपोच टाइम्स में छपे एक विश्लेषण के मुताबिक ऐसा बाहर से देखने में लगता है कि चीन में श्रमिक हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ विदेशी कंपनियों यानी एमएनसी में ही उन्हें हड़ताल करने की इजाजत दी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन विदेशी कंपनियों में हड़ताल की इजाजत देने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार की छवि में सुधार होगा। दुनिया को लगेगा कि चीन में आम आदमी के मौलिक अधिकारों का अब दमन नहीं हो रहा है। पिछले मई में जिन सात कंपनियों में हड़ताल हुए, उसमें से दो मामले को उदाहरण के तौर पर पेश किया जा सकता है। इन दो हड़तालों में से एक गुंगडांग प्रांत के होशान की जापानी होंडा कंपनी में हुई और दूसरी हेनान प्रांत के पिंगडिंगशन में चीनी के स्वामित्व वाली एक कपास के मिल में हुई।

होंडा के मजदूरों ने हड़ताल में विजय हासिल की और उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई जबकि चीनी स्वामित्व वाले कॉटन मिल में 1 जून को 2000 को 3000 पुलिसकर्मियों ने मजदूरों का बुरी तरह से दमन कर दिया।

हालांकि दोंनों ही जगहों पर मजदूरों ने सरकार मजदूर यूनियन पर मजदूरों को दबाने का आरोप लगाया।

पिंगडिंगशन में मजदूरों ने एशिया साप्ताहिक को

बताया कि यूनियन माफिया से भी बुरे हैं। होंडा के मजदूरों ने कहा कि सरकारी स्थानीय यूनियन ने मजदूरों से पैसे लिए लेकिन मजदूरों का ही दमन किया। इसलिए मजदूरों ने स्थानीय यूनियन में दोबारा चुनाव कराने और सभी अधिकारियों को फिर से नियुक्त किये जाने की मांग की।

मीडिया पर हमला

ठीक इसी समय कम्युनिस्ट पार्टी ने सतही तौर पर विदेशी कंपनियों हड़ताली मजदूरों के प्रति सहानुभूति दिखाई। वाणिज्य मंत्री ने अपना महत्व कम करते हुए कहा कि वे मीडिया से कुछ भी कहने की स्थिति नहीं रखते हैं।

उधर घरेलू मीडिया ने मई में जब होंडा में काम करने वाले मजूदरों के हड़तालों पर काफी कुछ छापा, उसी समय बीबीसी चाइना और हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग ने यह खबर प्रकाशित की कि चीन के सेंट्रल प्रोपोगेंडा डिपार्टमेंट ने इस बारे में निर्देश जारी किया है कि हड़ताल से जुड़ी खबरों को घरेलू मीडिया में जगह ना दिए जाएं।

चीन में सरकार को मिलने लगी है चुनौती

चीन के कई विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी नेतृत्व को मिलने वाली चुनौती के दमन के लिए सरकार ने स्ट्राइक हार्ड अभियान शुरू किया है। आर्थिक और राजनीति कमेंटेटर जैसन मा ने एनटीडीटीवी पर कहा कि वर्षों से साम्यवादी शासन के तले समाज में तनाव और विसंगति फैल रही है। पिछले दिनों स्कूलों में हुई हत्याओं और मजदूरों के लगातार हड़तालों की घटनाओं में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। इन सब बातों से चीन की सरकार को लगने लगा है कि जनता का असंतोष उग्र हो सकता है।

इन विरोध प्रदशनों के अलावा महंगाई की समस्या चीनी मजदूरों को पीड़ित कर रही है। पिछले कुछ दिनों में खास कर महंगाई काफी तेजी से बढ़ी है और सरकार ने आम जनता में फैल रही हिंसा को हिंसा से दबाया है।

सरकार के स्ट्राइक हार्ड अभियान में इसी मनोवृत्ति को देखा जा सकता है। कम से कम 7 महीनों तक सरकार इस प्रकार मजूदरों के रोष पर नियंत्रण रखेगी।

ताइवान में नेशनल सुन यात सेन विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शोइंग यंग ने भी कहा कि चीन में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उससे मजदूरों का विद्रोह करना तय है। और आधुनिक संचार तकनीक के कारण मोबाइल आदि इतने सस्ते मिल रहे हैं और इनसे आम आदमी का आपसी संवाद इस कदर बढ़ रहा है कि सरकार के लिए इस विद्रोह पर काबू पाना संभव नहीं रह जाएगा।

मेसर्स मा एंड यंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अस्थिरता को हिंसा से दबाने का उलटा असर हो सकता है।

बीजिंग विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर गुओ युहुआ का भी कुछ ऐसा ही मानना है। वे कहती हैं कि स्थानीय सरकार के द्वारा मजदूरों के दमन से वे क्षुब्ध हैं। उन्होंने कहा कि स्थिरता शब्द के प्रति चीनी सरकार की समझ को बदलने की जरूरत है। वह कहती हैं कि सरकार सोचती है कि दबाने से समस्या का समाधान हो जाएगा, जबकि आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करके ही स्थायित्व कायम की जा सकती है। प्रो. गुओ ने यह भी कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों और किसानों के जनाधार पर ही बनी थी, इसलिए इस मसले को यदि ठीक तरह से सुलझाया नहीं गया, तो पार्टी अपना जनाधार खो देगी।

इस बीच विभिन्न कंपनियों में मजदूरों का हड़ताल जून में भी जारी रहा। गंगझॉ में टोयोटा की आपूर्ति करने वाली डेंसो कॉर्प में 21 जून तक, तियानजिंग में टोयोडा गोसी में 17 जून और गंगडांग प्रांत में झोंगशन में होंडा लॉक में 9 जून तक हड़ताल जारी रहा। अन्य कई जगहों पर भी हड़ताल जारी रहा।

अमेरिका में भी इसे लेकर चिंता जताई जा रही है। रायटर के 14 जून की खबर के मुताबिक अमेरिका के सबसे बड़े श्रमिक संघ एएफएल–सीआईओ ओबामा को इस बाबत एक पत्र भेजने पर सोच रही है कि वे यह जांच करवाएं कि श्रमिकों के अधिकारों के साथ ज्यादती कर चीन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किसी तरह के लाभ की स्थिति में तो नहीं है।

आर्थिक और राजनीति कमेंटेटर जैसन मा ने एनटीडीटीवी पर कहा कि वर्षों से साम्यवादी शासन के तले समाज में तनाव और विसंगति फैल रही है। पिछले दिनों स्कूलों में हुई हत्याओं और मजदूरों के लगातार हड़तालों की घटनाओं में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। इन सब बातों से चीन की सरकार को लगने लगा है कि जनता का असंतोष उग्र हो सकता है।

चीन ने बांग्लादेश में रखा रणनीतिक कदम

अपने भाषण में डॉ. अग्निहोत्री ने कहा कि तिब्बत की आजादी की लड़ाई में साथ देना भारत की नैतिक जिम्मेदारी है। यह भारत की सीमा सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है। उन्होंने चीन की मानसिकता को मध्य युग की मानसिकता बताया, जब चीन दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में लगातार आक्रमण करता रहा था। उन्होंने कहा कि भारत को मजबूती से उठ खड़ा होना होगा, ताकि तिब्बत सहित वह अपने हितों की भी सुरक्षा कर सके।

(आईएएनएस, 15 जून, 2010)

चीन दक्षिण एशिया में लगातार अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाता जा रहा है। चीन ने अगला कदम रखा है बांग्लादेश में। चीन ने बांग्लादेश को चटगांव में डीप सी पोर्ट बनाने में मदद करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही वह ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सूचना देने पर भी सहमत हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत होकर भारत से गुजरते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है। इसके अलावा चीन ने बांग्लादेश को उसका पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने में भी मदद करने का आश्वासन दिया है। डेली स्टार में छपी खबरों के मुताबिक बांग्लादेश की यात्रा पर आए चीनी उपराष्ट्रपति और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण बातचीत हुई।

मार्च में शेख हसीना ने चीन की यात्रा की थी तब उसने कई मुद्दों पर चीन से सहयोग मांगा था, जिसमें से एक चटगांव से पूर्वी चीन के कुनमिंग तक सड़क का निर्माण भी था।

रणनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक चटगांव में पोर्ट निर्माण का प्रस्ताव चीन के ''स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'' रणनीति का हिस्सा है, जिसकी मदद से वह हिंद महासागर से होकर गुजरने वाले उसके समुद्री रास्तों की सुरक्षा करना चाहता है और अपने औद्योगीकृत पूर्वी चीन के हिस्से को तेल समृद्ध मध्यपूर्व से जोड़ना चाहता है।

चीन पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हंबंटोटा में बंदरगाह बना रहा है। वह पिछले कुछ सालों में म्यांमार में भी अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। पिछले साल बांग्लादेश में आवामी लीग के सत्ता संभालने के बाद यहां चीन के किसी आधिकारिक नेता की यह पहली यात्रा है। जी एक 35 सदस्यीय दल की अगुआई कर रहे हैं। इस यात्रा में वे एक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तहत चीन बांग्लादेश को 58 लाख डॉलर की सहायता देगा। पिछले कुछ सालों में चीन बांग्लादेश को मिलिट्री हार्डवेयर की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है।

बांग्लादेश को होने वाले निर्यात के मामले में भी चीनी ने भारत के मुकाबले बढ़त ले ली है। पिछले माह चीन ने बांग्लादेश के 5000 उत्पादों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया। उम्मीद की जा रही है कि चीन और बांग्लादेश के बीच व्यापार पिछले साल के 4.58 अरब डॉलर से बढ़कर 2010 में 5 अरब डॉलर हो जाएगा।

रोचक बात यह है कि चीन ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति का विरोध किया था। और 1975 में ही जाकर बांग्लादेश को मान्यता दी थी।

बीटीएसएम की अगुआई में तिब्बत जन जागृति कार्यक्रम

(आईटीसीओ, नई दिल्ली, 6 जून)

भारत तिब्बत सहयोग मंच यानी (बीटीएसएम) ने 2 से 5 जून 2010 को उत्तर भारत के दो राज्यों में तिब्बत के बारे में जागृति फैलाने के लिए एक अभियान संपन्न किया। इसके तहत बीटीएसएम के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. कुलदीप चंद और सचिव अरविंद गर्ग तथा भारत–तिब्बत समन्वय केंद्र (आईटीसीओ) दिल्ली के कोऑर्डिनेटर तेंजिन लेक्शे ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ और अलीगढ़ तथा उत्तराखंड के विकासनगर की यात्रा की। इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ऑफीसर्स ट्रेनिंग कैंप (ओटीसी) के सहयोग से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2 जून को डॉ. के सी अग्निहोत्री ने हापुड़ में ट्रेनिंग कैंप में शामिल 200 नौजवानों के समक्ष तिब्बत मामले पर भाषण दिया।

3 जून को वे अलीगढ़ गए और वहां कैंप के 400 प्रतिभागियों के सामने भाषण दिया। फिर 5 जून को डॉ. अग्निहोत्री ने विकास नगर में 400 से अधिक प्रतिभागियों के सामने भाषण दिया। इसके अलावा अगले तीन सप्ताह के दौरान उत्तर भारत के तीन अलग–अलग क्षेत्रों में भी इसी तरह के तीन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। अपने भाषण में डॉ. अग्निहोत्री ने कहा कि तिब्बत की आजादी की लड़ाई में साथ देना भारत की नैतिक जिम्मेदारी है। यह भारत की सीमा सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है। उन्होंने चीन की मानसिकता को मध्य युग की मानसिकता बताया,

जब चीन दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में लगातार आक्रमण करता रहा था। उन्होंने कहा कि भारत को मजबूती से उठ खड़ा होना होगा, ताकि तिब्बत सहित वह अपने हितों की भी सुरक्षा कर सके।

तिब्बतियों के समर्थन में खड़ा हुआ जनता दल (यू)

(तिब्बत डॉट नेट, धर्मशाला, 14 जून)

जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय महासचिव जावेद रजा ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी तिब्बतियों के पक्ष में है। रजा निर्वासित तिब्बती संसद के आमंत्रण पर दो दिनों के लिए इस शहर में आए थे। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जनता दल नेता शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडीस भारतीय संसद में प्रमुखता से तिब्बत का मुद्दा उठाते रहे हैं और दल के नेता इन दिनों तिब्बत पर सर्वदलीय संसदीय मंच में फिर से जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय नेता के स्वागत में बोलते हुए निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर डोलमा ग्यारी ने भारत के सभी राजनीतिक दलों के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि भारत यदि तिब्बत के मामले में और सक्रियता दिखाए तो तिब्बत का मामला और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने 1969 में तिब्बत मामले पर सभी पार्टियों का संसदीय दल बनाने में विशेष भूमिका निभाने के लिए जॉर्ज फर्नांडीस और मधु मिलानी के योगदानं को याद किया। तिब्बती सांसद वेनरेबल गेशे थुपतेन फेल्ग्ये ने कहा कि निर्वासित तिब्बती संसद भारतीय सांसदों के साथ तालमेल बढ़ाने के प्रयास के तहत रजा को फिर से धर्मशाला आमंत्रित करेगी। उन्होंने भारत सरकार से तिब्बत मामले को और ताकत के साथ उठाने का आग्रह किया। दो दिवसीय यात्रा में रजा तिब्बती स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से मिले और उन्होंने ध र्मशाला के विद्यालयों और अन्य संस्थानों की यात्रा की।

तिब्बती संगठन के सहयोग से जल और जलवायु परिवर्तन पर विशषज्ञों की एक वार्ता संपन्न

(तिब्बत डॉट नेट, धर्मशाला, 17 जून)

विशेषज्ञों की एक सभा में नई दिल्ली में बुधवार को जल और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एक गोष्ठी संपन्न हुई। इस गोष्ठी का आयोजन नवदान्या और कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज ने संयुक्त रूप से किया। यह जानकारी दिल्ली स्थित भारत–तिब्बत समन्वय केंद्र (आईटीसीओ) ने दी है।

गोष्ठी में नवदान्या की संस्थापक और निदेशक डॉ. वंदना शिवा, भारत सरकार में जल संसाधन विभाग के पूर्व सचिव डॉ. रामास्वामी अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार एवं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के मानद प्रोफेसर और पत्रकारिता के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित बी जी वर्गीज, पत्रकार और तिब्बत मामलों के विशेषज्ञ विजय क्रांति और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, धर्मशाला के सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के पर्यावरण एवं विकास डेस्क के कार्यकारी प्रमुख तेंजिंग नोर्बू ने भाग लिया।

वंदना शिवा ने भारत में जल संकट और पंजाब में भूमिगत जल स्तर में हो रही तेज गिरावट, और भारत के उत्तरी बेल्ट जैसे जंस्कर रेंज में हिमनदियों के पिघलने का मामला उठाया। रामास्वामी अय्यर ने जलवायु परिवर्तन पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल की रिपोर्ट के बारे में बताया और कहा कि जल संकट मानव ने खुद अपने लालच की वजह से पैदा किया है।

बी जी वर्गीज ने चीन में बांध निर्माण का मामला उठाया। लेकिन उससे अधिक उन्होंने भारत में संसाधनों की कमी पर ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि भारत में जलवायुविद हिमनदियों के जानकार और मौसम वैज्ञानिकों की घोर कमी है। विजय क्रांति ने कहा कि तिब्बत में बड़े पैमाने पर हो रहे जनसंख्या स्थानांतरण के कारण पारिस्थिकीय संकट पैदा हो रहा है। तेंजिंग नोरबू ने भी चीन में बांधों के निर्माण, ग्लोबल वार्मिंग और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि तिब्बत में तापमान के बढ़ने से वहां परमाफ्रॉस्ट पिघलने की घटना बढ़ेगी और वहां की पारिस्थिकी को स्थाई नुकसान पहुंचेगा।

बी जी वर्गीज ने चीन में बांध निर्माण का मामला उठाया। लेकिन उससे अधिक उन्होंने भारत में संसाधनों की कमी पर ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि भारत में जलवायुविद हिमनदियों के जानकार और मौसम वैज्ञानिकों की घोर कमी है। विजय क्रांति ने कहा कि तिब्बत में बड़े पैमाने पर हो रहे जनसंख्या स्थानांतरण के कारण पारिस्थिकीय संकट पैदा हो रहा है।

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आं

1 हवन में शामिल होते हुए परम पावन दलाई लामा। परम पावन के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे ने किया। यह हवन कार्यक्रम मैकल्योडगंज के स्थानीय भारतीय नागरिकों द्वारा "निर्वासित हांग)

2 "भारत–तिब्बत मैत्री के 50 साल" पूरे होने के उपलक्ष्य में धर्मशाला के मुख्य मंदिर में 15 ज की उपस्थिति में पारंपरिक भंडारे में भोजन परोसते हुए स्थानीय भारतीय नागरिक (फोटो–

3 केगुदो के भूकंप पीड़ितों के लिए आयोजित विशेष प्रार्थना सभा की अध्यक्षता करते हुए पर फोटो–नामग्याल सेवांग/टिबेटनेट

4 परम प्रतिष्ठित 17वें ग्यालवा कर्मापा ओर्गेन त्रिनले दोरजी सिद्धबारी, धर्मशाला के गुटो मठ

5 थ्री रिवर्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना करने वाले तिब्बती कला संग्रहक कर्मा किया गया है। (फोटो– Woeser.middle-way.net)

6 धर्मशाला में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान जनता दल (यू) के पार्टी सचिव दूसरी), वेन गेशे थुपटेन फेलगे (दाएं से पहले) और श्रीमती गवांग ल्हामो (बाएं से पहले)

7 कालोन केसांग यांगक्यी टाकला (बीच में) ने रविवार, 30 मई को धर्मशाला में शोडंग की संसद सदस्य ग्यालरोंग दावा सेरिंग, वेन मोनलम थारचिन और नागा सांगये तेनदार भी दि

8 नई दिल्ली में 16 जून, 2010 को जल एवं जलवायु परिवर्तन पर आयोजित एक सामूहिक रामास्वामी अय्यर और श्री तेनजिन नोर्बू। फोटोः आईटीसीओ

9 ग्रीन पार्टी के सांसद रसेल नॉर्मन अपने हाथों में तिब्बत का फटा हुआ झंडा लिए हुए। रसे शामिल अधिकारियों ने उनके हाथ से तिब्बती झंडा छीनकर उसे फाड़ दिया।

10 शॉडंग की फाइल फोटो

(9)

(8)

(3)

(4)

ंख से तिब्बत

जीवन के लिए इस हवन का संचालन 15 जून, मंगलवार को मुख्य तिब्बती मंदिर में हिंदू पुजारियों तिब्बतियों से दोस्ती के 50 साल पूरे होने" के अवसर पर आयोजित किया गया था। (फोटो–डेविड

ून, 2010 को आयोजित एक समारोह के दौरान परम पावन दलाई लामा (बीच में सामने बैठे हुए) डेविड हांग)

म पावन दलाई लामा। यह सभा 1 जून, 2010 को धर्मशाला के सुंगलागखांग में आयोजित की गई।

में अपना 26वां जन्मदिन मनाते हुए। फोटो–नामग्याल सेवांग/टिबेटनेट

सामदुप को समाधियों को लूटने और सांस्कर्षतिक कलाकर्षतियों को चुराने के आरोप में गिरफ्तार

जावेद राजा (दाएं से दूसरे), निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर सुश्री डोलमा ग्यारी (बाएं से

ुस्तक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर तस्वीर में डिप्टी स्पीकर डोलमा ग्यारी (दाएं से दूसरी), ख रहे हैं। फोटो–नामग्याल सेवांग/टिबेटनेट

चर्चा में शामिल होते हुए बाएं से श्री विजय क्रांति, श्री बी जी वर्गीज, डॉ. वंदना शिवा, डॉ.

ल जब संसद में तिब्बत का झंडा लेकर पहुंचे तो चीनी उपराष्ट्रपति जी जिनपिंग के सुरक्षा दस्ते में

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(5)

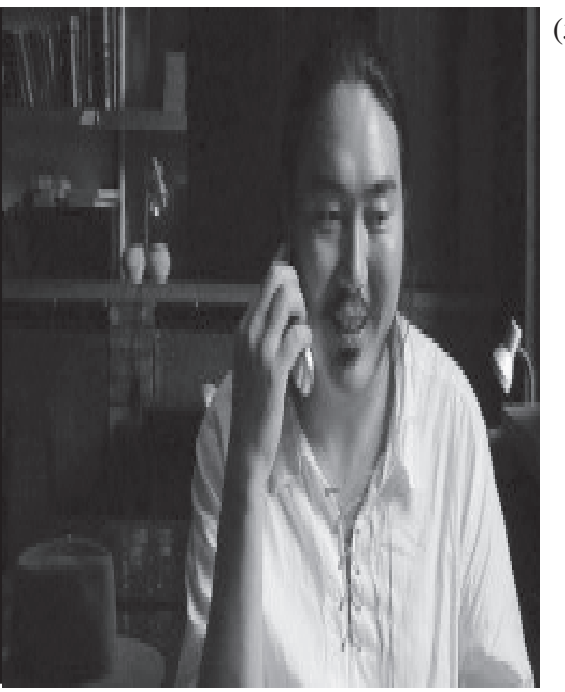

(7)

(6)

चीन में प्रतिबंधित तिब्बती पुस्तक का निवार्सन में पुनर्प्रकाशन

धर्मशाला में तिब्बती महिला संगठन गु चु सुम और स्टूडेंट फॉर फ्री तिब्बत–इंडिया ने 10,000 हस्ताक्षरों वाली एक याचिका बीजिंग में चीनी अधिकारियों और भारत में चीनी दूतावास को भेजी। याचिका कोरियर और फैक्स के माध्यम से भेजी गई। इसी तरह की एक याचिका तेंजिंग देलेक रिंपोछे के गृहनगर पूर्वी तिब्बत के खम (चीनी में अब इसे सिचुआन प्रांत कहते हैं) प्रांत में भी पिछले साल 40,000 हस्ताक्षरों के साथ भेजी गई थी।

(टिबेट डॉट नेट, धर्मशाला, 1 जून)

चीन में प्रतिबंधित पुस्तक 'नाम–सा गो–चेद' को फिर से प्रकाशित कर रविवार को धर्मशाला में लोकार्पित किया गया। पुस्तक का पुनर्प्रकाशन और लोकार्पण दो संगठनों धोमय अलायंस फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस और सेंट्रल धोमय एसोसिएशन ने मिलकर किया है। पुस्तक के लेखक ताग्याल ने इस पुस्तक में चीन सरकार के दमन के खिलाफ साल 2008 में तिब्बत के नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध का लेखा–जोखा प्रस्तुत किया है। ताग्याल शोगदंग नाम से लिखते हैं। चीन सरकार ने उन्हें इस पुस्तक को लिखने के जुर्म में अप्रैल में तिब्बत के सिलिंग स्थित उनके कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया था।

लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कालोन केसांग यांग्की टाकला और विशेष अतिथि के रूप में डिप्टी स्पीकर डोलमा ग्यारी ने भाग लिया।

कालोन टाकला ने अपने और अपने परिवार की जान की बाजी लगाकर पुस्तक लिखने के लिए शोगदंग की जमकर तारीफ की। डिप्टी स्पीकर डोलमा ग्यारी ने कहा कि निर्वासित सरकार शोगदंग और तिब्बत के लिए संघर्ष कर रहे तिब्बतियों की आभारी है। निर्वासित तिब्बतियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।

पुस्तक लोकार्पण समारोह में तिब्बत के निर्वासित संसद सदस्यों में से गेशे मोनलम थार्चिन, गेशे शेरिंगपो घासी, लोपोन सोनम तेनफेल और ग्यालरोंग दावा शेरिंग मौजूद थे। लोकार्पण के बाद इस पुस्तक पर हुई समूह चर्चा में लाइब्रेरी ऑफ टिबेटन वर्क्स एंड आर्काइव्स और नॉर्लिंग कल्चरल इंस्टीट्यूट के रिसर्च डिपार्टमेंट के शोधार्थियों और तिब्बती अध्ययन के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

भिक्षु को मुक्त करने के लिए चीन सरकार से तिब्बतियों और तिब्बत समर्थकों का लिखित आग्रह

(फायुल.कॉम, धर्मशाला, 16 जून)

चीन में आजीवन कारावास की सजा झेल रहे तिब्बती बौद्ध भिक्षु तेंजिंग देलेक रिंपोछे को मुक्त कराने के लिए यहां तिब्बतियों और उनके समर्थकों ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धर्मशाला सहित दुनिया भर में तिब्बतियों और उनके समर्थकों ने करीब 40,000 हस्ताक्षरों वाली एक याचिका चीनी दूतावास को भेजी, जिसमें तेंजिंग देलेक रिंपोछे की गिरफ्तारी को अनुचित बताकर उन्हें छोड़ने का आग्रह किया गया। धर्मशाला में तिब्बती महिला संगठन गु चु सुम और स्टूडेंट फॉर फ्री तिब्बत–इंडिया ने 10,000 हस्ताक्षरों वाली एक याचिका बीजिंग में चीनी अधिकारियों और भारत में चीनी दूतावास को भेजी। याचिका कोरियर और फैक्स के माध्यम से भेजी गई। इसी तरह की एक याचिका तेंजिंग देलेक रिंपोछे के गृहनगर पूर्वी तिब्बत के खम (चीनी में अब इसे सिचुआन प्रांत कहते हैं) प्रांत में भी पिछले साल 40,000 हस्ताक्षरों के साथ भेजी गई थी। इस याचिका को लेकर तेंजिंग देलेप रिंपोछे के परिवार के सदस्य पिछले साल दिसंबर में बीजिंग में अधिकारियों के पास जा रहे थे, जिन्हें चेंगदू में रोक लिया गया था।

गु चू सुम आंदोलन की अध्यक्ष गावांग वोबर ने कहा कि चीन के कारावास में तेंजिंग देलेप रिंपोछे के साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अब उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया है। इसीलिए जल्द से जल्द अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से उनके साथ व्यवहार किया जाए। गावांग वोबर भी पहले चीन की जेल में रह चुकी हैं।

परमपावन दलाई लामा ने केगुडो के मृतकों की याद में विशेष प्रार्थना सभा की अगुआई की

(टिबेट डॉट नेट, धर्मशाला, 1 जून)

परम पावन दलाई लामा ने यहां केगुडो में आए भूकंप की विभीषिका के 49वें दिन आयोजित विशेष प्रार्थना सभा की अगुआई की। तिब्बत के केगुडो में 14 अप्रैल को आए भूकंप में हजारों लोग मारे गए थे। इस अवसर पर मुख्य मंदिर

सुगलागखांग में हजारों तिब्बती इकट्ठा हुए और मृतकों के परिवार जनों के दुख दूर करने के लिए और घायलों के जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना सभा में सभी तिब्बती प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। कशग के निर्देशानुसार पूरी दुनिया में तिब्बतियों ने इसी समय प्रार्थना सभा की।

काठमांडू के तिब्बत शरणार्थी कल्याण कार्यालय से मिली सूचना के अनुसार वहां रह रहे तिब्बतियों ने भी अपने आसपास के मंदिरों में इकट्ठा होकर केगुडो के पीड़ितों लिए प्रार्थना की। छोजोर तिब्बती बस्ती के तिब्बती अपने सामुदायिक भवन में इकट्ठा हुए, जबकि ग्यालफाक में रहने वाले तिब्बती स्वयंभू में किदोंग थुकजे छोलिंग ननरी में इकट्ठा हुए, जहां परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधि त्रिनले ग्यात्सो ने प्रार्थना सभा में भाग लिया। इससे पहले परमपावन दलाई लामा ने 27 अप्रैल और 4 मई को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा की अगुआई की थी।

यहां रह रहे तिब्बतियों ने युशु भूकंप दान समिति के माध्यम से केगुडो में चलाए जा रहे राहत कार्यों में योगदान करने के लिए अपनी तरफ से दान भी किया।

परमपावन दलाई लामा ने भारत–तिब्बत मैत्री उत्सव में हिस्सा लिया

(फायुल डॉट कॉम, धर्मशाला, 15 जून)

निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु परमपावन दलाई लामा ने तिब्बतियों और भारतीयों की मैत्री और सामंजस्य के 50 साल पूरे होने की खुशी में यहां आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में भारतीय पुजारियों ने हवन, प्रार्थना किया और दलाई लामा के लंबे जीवन और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी, आयोजन समिति के सदस्य और हजारों तिब्बती, भारतीय नागरिक और पर्यटकों ने तिब्बतियों के प्रमुख मंदिर सुगलागखांग के प्रांगण में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रमुख पुजारी स्वामी आनंद जी ने कहा, "हमने पूजा में माननीय दलाई लामा के लंबे जीवन और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की और तिब्बत सहित दुनियाभर में रह रहे तिब्बतियों के बेहतर जीवन के लिए प्रार्थनाएं कीं हैं।"

दिनभर चले इस समारोह में मैकलॉडगंज में रह रहे भारतीयों के 6 संगठनों की ओर से आम लोगों के लिए एक भंडारे का भी आयोजन किया गया। माननीय दलाई लामा, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अधिकारियों को भी मंदिर प्रांगण में भोजन कराया गया।

इस समारोह का आयोजन भारत–तिब्बत मैत्री समाज (आईटीएफएस), और मैकलॉडगंज के होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, बाग्सू टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन, और ट्रेकर्स एसोसिएशनों ने मिलकर किया।

आईटीएफएस के अध्यक्ष अजय सिंह मनकोटिया ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह आयोजन धर्मशाला में साथ ही हिमाचल प्रदेश और पूरे भारत में रह रहे तिब्बतियों और भारतीयों की 50 साल की मित्रता की एक मिसाल है। यह आयोजन परमपावन दलाईलामा के सम्मान में है और यह जताने का एक प्रयास है कि उनकी मौजूदगी से हम सभी को खुशी मिल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों से दलाई लामा की मौजूदगी और उनके मार्गदर्शन में दोनों ही समुदाय शांति के साथ रहे रहे हैं। उनकी मौजूदगी ने धर्मशाला को एक आध्यात्मिक नगरी बना दिया है। निर्वासित तिब्बती नेता ने आयोजकों और स्थानीय नागरिकों को पूजा और इस समारोह के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने तिब्बतियों से कहा कि वे उन मूल्यों को बरकरार रखें जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता और विकास के साथ ही हमें उन मूल्यों को भी सहेज कर रखना है, जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है। उन्होंने कहा कि इन्हीं जीवन मूल्यों के कारण हमें दुनिया भर में प्यार और पहचान मिला है। अगर हम इन मूल्यों को खो देंगे, तो यह बहुत दुखदायी होगा। 1959 में चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लिए जाने के बाद 1960 से दलाई लामा भारत के इस पहाडी सुरम्य नगरी में निर्वासित जीवन बिता रहे

छोजोर तिब्बती बस्ती के तिब्बती अपने सामुदायिक भवन में इकट्ठा हुए, जबकि ग्यालफाक में रहने वाले तिब्बती स्वयंभू में किदोंग थुकजे छोलिंग ननरी में इकट्ठा हुए, जहां परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधि त्रिनले ग्यात्सो ने प्रार्थना सभा में भाग लिया। इससे पहले परमपावन दलाई लामा ने 27 अप्रैल और 4 मई को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा की अगुआई की थी।

हैं। अप्रैल में दलाई लामा के मैकलॉडगंज आने के 50 साल पूरा होने की खुशी में निर्वासित तिब्बतियों ने स्थानीय लोगों और हिमाचल प्रदेश की सरकार के प्रति सम्मान जताने के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम "धन्यवाद हिमाचल" का आयोजन किया था। दलाई लामा 1959 में वर्तमान उत्तराखंड के मसूरी में आकर टिके थे। एक साल बाद वे हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला आ गए। तब से निर्वासित तिब्बती सरकार का यही ठिकाना बना हुआ है। धर्मशाला और हिमाचल के अलग–अलग 14 बस्तियों में लगभग 35000 तिब्बती रह रहे हैं।

वह अभी उस दुख से उबर भी नहीं पाई थी और अंतिम संस्कार का रस्म पूरा कर रही थी।

ग्यालवा करमापा ने हजारों श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देकर मनाई अपनी 26वीं सालगिरह

तिब्बत.नेट, 28 जून 2010, धर्मशाला – 17वें ग्यालवा करमापा उर्गेन ट्रिनले दोर्जी ने अपने 26वीं सालगिरह पर उनके दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर 26 जून, शनिवार को धर्मशाला के निकट सिधबरी में ग्यूटो तांत्रिक मठ में उनके दर्शन करने हजारों श्रद्धालु आए थे।

उनके दर्शन करने आए हजारों श्रद्धालुओं में से कई ताइवान, चीन और अन्य कई देशों से थे। धर्मशाला के आसपास रहने वाले हजारों तिब्बती और बड़ी संख्या में भिक्षुगण भी उनके दर्शन करने आए थे।

मठ के कर्मचारी, निर्वासित तिब्बती संसद सदस्य, धर्मशाला तिब्बती कल्याण अधिकारी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें इस अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर तिब्बेतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ से तिब्बती संस्कृति के लोक नृत्यों का आयोजन किया गया।

वह अभी उस दुख से उबर भी नहीं पाई थी और अंतिम संस्कार का रस्म पूरा कर रही थी। जांच एजेंसी ने न सिर्फ उससे और उसके परिवार से ढाका में पूछताछ की, बल्कि उसके गांव फेनी में भी उसके अन्य परिवारजनों से पूछताछ की गई।

चीनी उपराष्ट्रपति के दौरे से पहले बांग्लादेश में तिब्बती कार्यकर्ता पर पुलिसिया अत्याचार

(फायुल.कॉम, धर्मशाला, 11 जून)

13 जून को होने वाले चीनी उपराष्ट्रपति के बांग्लादेश के दौरे से ठीक पहले बांग्लादेश की एक तिब्बत मामले की कार्यकर्ता को पुलिसिया अत्याचार का सामना करना पड़ा। चीनी उपराष्ट्रपति के दौरे से पहले स्टूडेंट फॉर फ्री तिब्बत की बांग्लादेश शाखा की सदस्य वासफिया नजरीन और उसके परिवार के साथ गुलशन थाने की पुलिस की विशेष शाखा और एनएसआई सदस्यों से पिछले छह दिन में कई बार पूछताछ की गई है। यह जानकारी बांग्लादेश के मानवाधिकार संगठन के वेबसाइट से मिली है। www.unheardvoice.net पर डाली गई सामग्री के मुताबिक नजरीन की दादी का 7 जून को ही देहांत हुआ है। वह अभी उस दुख से उबर भी नहीं पाई थी और अंतिम संस्कार का रस्म पूरा कर रही थी। जांच एजेंसी ने न सिर्फ उससे और उसके परिवार से ढाका में पूछताछ की, बल्कि उसके गांव फेनी में भी उसके अन्य परिवारजनों से पूछताछ की गई।

वेबसाइट पर छपी सामग्री के अनुसार नजरीन के वकील और मित्रों ने ऐसे वक्त उससे सहानुभूति जताई है। नजरीन फिलहाल अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन केयर में काम कर रही है। बांग्लादेश के अधिकारियों को संदेह था कि नजरीन चीनी उपराष्ट्रपति के बांग्लादेश दौरे के समय विरोध प्रदर्शन कर सकती है।

नजरीन के मित्रों का कहना है कि पुलिस ने नजरीन पर अत्याचार करना तब शुरू किया, जब उसने ड्रिक गैलरी के साथ मिलकर एक प्रदर्शनी ''इंटू एक्साइलः तिब्बत 1949–2009'' का आयोजन किया। नवंबर 2009 में चीनी दूतावास के दबाव में पुलिस ने कार्यक्रम को बीच में ही बंद करा दिया था। बांग्लादेश उन कुछ गिने चुने मुस्लिम देशों में से एक है, जहां तिब्बत के मामले को उठाया जाता है।

न्यूजीलैंड के सांसद पर चीनी सुरक्षा जवान का हमला

(एपी, वेलिंगटन, न्यूजीलैंड 18 जून)

न्यूजीलैंड के एक सांसद ने आरोप लगाया है कि एकल विरोध प्रदर्शन के दौरान एक चीनी सुरक्षा जवान ने उसे धक्का दिया, उस पर छतरी से हमला किया और उसके हाथों से तिब्बती झंडा छीन लिया। ग्रीन पार्टी के नेता रसेल नॉर्मन ने आरोप लगाया है कि यह घटना संसद की सीढ़ी

पर हुई, जब चीनी उपराष्ट्रपति जी जिपिंग संसद के अधिकारियों से मिलने के लिए आए थे। नॉर्मन ने कहा कि वे तिब्बत की आजादी के नारे लगा रहे थे, ठीक उसी समय चीनी सुरक्षा गार्डों ने उन्हें घेर लिया। नॉर्मन ने पत्रकारों से कहा कि चीनी सुरक्षा गार्डों ने उन्हें कोहनी से धक्का देकर किनारे कर दिया, उनके सिर पर छतरी से वार किया और उनके हाथ से तिब्बती झंडा छीन कर उसे पैरों से कुचल दिया।

संसद के स्पीकर लॉकवुड स्मिथ ने इस मामले की छानबीन का आदेश दे दिया है। इसके बाद नॉर्मन ने भी इस बारे में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और दोषी चीनी सुरक्षा जवान का हिरासत में लेने की मांग की। ऐसा लगता है कि नॉर्मन के विरोध प्रदर्शन को चीनी प्रतिनिधिमंडल ने अपमान के तौर पर लिया। ग्रीन पार्टी के ही एक अन्य सांसद के साथ पहले भी इसी तरह की घटना घट चुकी है। जब 2005 में चाइना नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के चेयरमैन वु बांगुओ के न्यूजीलैंड दौरे के समय चीनी सुरक्षा जवानों ने न्यूजीलैंड पुलिस से उन्हें और उनके हाथ में मौजूद तिब्बती झंडा हटाने की मांग की थी और उन्हें चीनी नेता से मिलने से रोकने को कहा था। उस समय तिब्बती झंडे को दिखाना चीनी अतिथि के लिए अपमान के तौर पर लिया गया था। हालांकि, प्रधानमंत्री जॉन की ने नॉर्मन के विरोध प्रदर्शन के अधिकारों का समर्थन किया है।

अंतरराष्ट्रीय सांसदों के समूह ने जी 20 नेताओं से किया तिब्बत मसला निपटाने का आग्रह

(फायुल डॉट कॉम, धर्मशाला, 24 जून)

दुनिया के 30 संसद के करीब 133 सांसदों के समूह ने जी 20 नेताओं से तिब्बत मसले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। पिछले साल रोम में पांचवें वर्ल्ड पार्लियामेंटेरियंस कनवेंशन ऑन तिब्बत के मौके पर तिब्बत पर इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को आमंत्रित किया गया गया था। इस आयोजन को तिब्बतियों के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भी संबोधित किया था। इस साल जून में वर्ल्ड पार्लियामेंटेरियंस की पहली बैठक ब्रुसेल्स में हुई थी, जिसमें इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत को नेटवर्क का सचिवालय बनाया गया था। तिब्बत के निर्वासित संसद के स्पीकर पेम्पा शेरिंग ने कहा कि इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन तिब्बत और इसके सचिवालय का गठन एक अच्छा कदम है, इससे तिब्बत मसले के बेहतर कोऑर्डिनेशन में मदद मिलेगी और बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए काम करने में मदद मिलगी।

सांसदों के समूह ने कनाडा के प्रधान मंत्री स्टीफन हार्पर को एक पत्र लिखा, जिसमें तिब्बतियों की सुरक्षा और पहचान के विकास की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि यह चीन के संविधान में मौजूद वर्तमान स्वायत्तता के प्रावधान के तहत ही हासिल किया जा सकता है। 26 और 27 जून को टोरंटो में जी20 के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ ने भी भाग लिया।

ग्लोबल वार्मिंग से सूख सकती हैं एशिया की बड़ी नदियां

(एएफपी, बीजिंग, जून 10, 2010)

तिब्बत के पठारों में रहने वालें हजारों तिब्बतियों का जीवन खतरे में है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के कारण एशिया की तीन बड़ी नदियों के जल स्रोत सूख सकते हैं।

क्विंघई–तिब्बत के पठारों के चारों ओर खड़े पहाड़ों पर ग्लेशियर घटते जा रहे हैं और परमाफ्रॉस्ट(बर्फ की स्थायी परत) पिघल रहा है, इससे घास भूमि और नम भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। इसके कारण एशिया की तीन बड़ी नदियों यांग्जे,, येलो और मेकांग के सूखने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित पर्यावरण कार्यकर्ता ने चेतावनी दी है कि नदियों के सूखने से इस क्षेत्र में खाद्य संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में नदियों से बड़े पैमाने पर धान और गेहूं की खेती होती है।

यांग्जे नदी के जल भरण क्षेत्र में एक सर्वे दल के मुखिया और चीन के सरकारी वैज्ञानिक जिन

ऐसा लगता है कि नॉर्मन के विरोध प्रदर्शन को चीनी प्रतिनिधिमंडल ने अपमान के तौर पर लिया। ग्रीन पार्टी के ही एक अन्य सांसद के साथ पहले भी इसी तरह की घटना घट चुकी है। जब 2005 में चाइना नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के चेयरमैन वु बांगुओ के न्यूजीलैंड दौरे के समय चीनी सुरक्षा जवानों ने न्यूजीलैंड पुलिस से उन्हें और उनके हाथ में मौजूद तिब्बती झंडा हटाने की मांग की थी और उन्हें चीनी नेता से मिलने से रोकने को कहा था।

अप्रैल में थाइलैंड के प्रधानमंत्री अभिसित विजाजिवा ने एक क्षेत्रीय सम्मेलन में चेतावनी देते हुए कहा था कि पानी के अधिकाधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण मेकांग नदी पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सही प्रबंधन नहीं किया गया तो मेकांग नदी मर जाएगी। इस साल के शुरू में उत्तरी थाईलैंड और लाओस में मेकांग का जल स्तर पिछले 50 सालों में सबसे अधिक नीचे गिर गया था।

युआनहोंग ने भी एएफपी से कहा कि ग्लेशियरों का पिघलना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि जिस गति से ग्लेशियर पिघल रहा है, उस गति से अगले 10 सालों में 30 फीसदी ग्लेशियर पिघल जाएंगे। यदि ग्लेशियर अधिक तेजी से पिघले तो स्थिति और खराब हो जाएगी।

यह क्षेत्र येलो नदी में 50 फीसदी पानी का योगदान करता है, यांग्जे में 25 फीसदी और मेकांग में 15 फीसदी पानी का योगदान करता है। इन तीन नदियों के बेसिन में 58 करोड़ लोग रहते हैं और यहां बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की पैदावार होती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहां का भूमिगत जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है और यहां सूखा पड़ रहा है।

2005 में चीन ने इस क्षेत्र में मिट्टी का क्षरण रोकने के लिए 1.1 अरब डॉलर का कार्यक्रम शुरू किया। इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय संरक्षण कार्यक्रम माना जा रहा है।

जिन का कहना है कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता घट जाएगी, जिससे मिट्टी का क्षरण होने लगेगा। साथ ही मिट्टी सूखने से चूहों की आबादी बढ़ेगी, जो मिट्टी के क्षरण की गति को और बढ़ाएगी। संरक्षण कार्यक्रम के तहत लगभग 20,000 चरवाहों को इस साल की शुरुआत में ग्रासलैंड से हटाकर सथायी गांवों में स्थापित किया गया है। ग्रासलैंड में मवेशियों के चराने पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन इसके कारण इन चरवाहों का सदियों पुराना पेशा खत्म हो गया है।

सरकारी आंकड़ों और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक युसुफ प्रशासनिक क्षेत्र में रह रहे लगभग 2,70,000 की आबादी का लगभग आधा हिस्सा मवेशियों का चराकर अपनी आजीविका चलाती है। एएफपी ने जब युसुफ एनवॉयरमेंटल प्रोटेक्शन एसोसिएशन के अधिकारियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि सूखा और घासभूमि के घटने के साथ ही यहां झील और नम भूमि भी सूख रहे हैं।

क्विंघई इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन हेजार्ड्स एंड एंनवॉयरमेंट के जल विशेषज्ञ वांग जेंक्सू ने कहा कि 1976 से 2008 के बीच तीन नदियों के बेसिन में वेटलैंड, मार्शलैंड और स्वैंपलैंड 32 फीसदी सिमट गए हैं।

वांग ने कहा कि झील 228 वर्गकिलोमीटर छोटे हो गए हैं, जो कि कुल झील क्षेत्रफल का 8.6 फीसदी है। वांग की संस्था चाइना एकेडमी ऑफ साइंस से मान्यता प्राप्त है।

अप्रैल में थाइलैंड के प्रधानमंत्री अभिसित विजाजिवा ने एक क्षेत्रीय सम्मेलन में चेतावनी देते हुए कहा था कि पानी के अधिकाधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण मेकांग नदी पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सही प्रबंधन नहीं किया गया तो मेकांग नदी मर जाएगी। इस साल के शुरू में उत्तरी थाईलैंड और लाओस में मेकांग का जल स्तर पिछले 50 सालों में सबसे अधिक नीचे गिर गया था। जिससे भोजन, यातायात और पेय जल के लिए इस नदी पर निर्भर आबादी सकते में आग गई थी। लेकिन थाई रिसॉर्ट शहर हुआ हिन में चल रहे सम्मेलन में चीन ने इनकार किया कि घटते जल स्तर के लिए चीन की नीतियां (बांधों का निर्माण और जल का अधिकाधिक दोहन) जिम्मेदार हैं। एक प्रतिष्ठित अमेरिकी पर्यावरण विशेषज्ञ लिस्टर ब्राउन ने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन और इसके आस पास के क्षेत्र में फसलों की पैदावार को बहुत नुकसान होगा और एशिया में बड़ा खाद्य संकट आएगा।

ब्राउन ने कहा कि हिमालय और तिब्बत के पठार में ग्लेशियरों के लगातार घटने के कारण खाद्य सुरक्षा पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

जल पर बवंडर

ब्रह्म चेलानी (टीओआई, 29 जून, 2010)

चीन से मिले नए संकेत बताते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की धाराओं को मोड़ने की उसकी योजना के तहत इस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह बांध नदी के कथित ग्रेट बेंड (मोड़) पर बनाया जाएगा जो उत्तर–पूर्वी भारतीय सीमा के पास तिब्बत में स्थित है। चीन की सार्वजनिक कंपनी हाइड्रो चाइना की वेबसाइट पर दिए गए इस बांध की नवीनतम योजना और नक्शे के अनुसार बड़े पैमाने पर जल को इकट्ठा करने वाले इस बांध से 38,000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा जो वहां के तीन जॉर्ज डैम के संयुक्त उत्पादन से भी दोगुना होगा। इसकी तुलना अगर भारत से की जाए तो यह बांध भारत के कुल संसाधनों से पैदा हो रही मौजूदा बिजली के करीब एक–चौथाई हिस्से का अकेले उत्पादन करेगा। जल अब भारत–चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मसला बनता जा रहा है और यह दोनों देशों में भविष्य में अनबन का संभावित मसला बन सकता है। चीन और भारत पहले से ही जल की तंगी वाले अर्थव्यवस्था हैं। बड़े पैमाने पर फैले खेतों की सिंचाई, जल की भारी खपत वाले उद्योग और बढ़ते मध्यम वर्ग से आने वाली खपत की वजह से ज्यादा से ज्यादा जल हासिल करने का संघर्ष बढ़ गया है। वास्तव में दोनों देश अब ऐसे स्थायी जल संकट वाले दौर में प्रवेश कर रहे हैं जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता के हिसाब से मध्यपूर्व के देशों में होने वाली जल की तंगी जैसा ही होगा।

जल की मांग यदि इसी तेजी से बढ़ती रही तो जो गंभीर संकट आएगा उससे दोनों देशों में हो रही तेज आर्थिक बढ़त सुस्त पड़ सकती है। इससे खाद्यान्न के लिहाज से आत्मनिर्भर भारत और चीन काफी हद तक आयातक देश बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह वैश्विक खाद्य संकट की शुरुआत होगी। चीन के मुकाबले भारत में ज्यादा खेतिहर भूमि है (चीन के 13.71 करोड़ हेक्टेयर की तुलना में यहां 16.05 करोड़ हेक्टेयर), लेकिन भारत की ज्यादातर नदियों का स्रोत चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत में है। तिब्बत के पठार पर फैली विशाल हिमनदियां, बड़े पैमान पर भूमिगत सोते और ऊंचे अक्षांश पर होने की वजह से तिब्बत दुनिया में ताजे जल का सबसे बड़ा भंडार है। वास्तव में गंगा के अलावा एशिया की सभी प्रमुख नदियां चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत पठार से निकलती हैं। यहां तक कि गंगा की मुख्य सहायक नदियां भी तिब्बत से बहकर आती हैं। लेकिन अब चीन तिब्बत के पठार पर कई बड़े अंतर घाटी और अंतर नदी जल हस्तांतरण परियोजनाएं शुरू कर रहा है जिससे भारत और अन्य देशों तक बहने वाली अंतरराष्ट्रीय नदियों के लिए संकट खड़ा होने जा रहा है। चीन ने जिस तरह से चुपके से तिब्बत में हाइड्रो इंजीनियरिंग परियोजनाएं शुरू की हैं उससे किसी और देश के मुकाबले सबसे ज्यादा नुकसान भारत के हितों को हो रहा है। हालांकि, ब्रह्मपुत्र की धाराओं को मोड़ने का सबसे ज्यादा गंभीर असर संभवतः बांग्लादेश पर होगा। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और चीन द्वारा इसकी धाराओं को मोड़ने से बांग्लादेश के बड़े हिस्से पर पर्यावरण का भारी विनाश होगा। वास्तव में चीन मेकांग, सालवीन, ब्रह्मपुत्र, इर्तिश–इली जैसी प्रमुख नदियों पर जिस तरह से बड़े बांध बना रहा है उसको लेकर कजाकिस्तान, रूस, भारत और इंडो–चीन प्रायद्वीप के इसके सभी तटवर्ती पड़ोसी देशों से जल–विवाद

जल अब भारत–चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मसला बनता जा रहा है और यह दोनों देशों में भविष्य में अनबन का संभावित मसला बन सकता है। चीन और भारत पहले से ही जल की तंगी वाले अर्थव्यवस्था हैं। बड़े पैमाने पर फैले खेतों की सिंचाई, जल की भारी खपत वाले उद्योग और बढ़ते मध्यम वर्ग से आने वाली खपत की वजह से ज्यादा से ज्यादा जल हासिल करने का संघर्ष बढ़ गया है।

शुरू हो गया है।

मार्च, 2009 में तिब्बत की क्षेत्रीय सरकार ने ब्रह्मपुत्र पर कई नए बड़े बांध बनाने की योजना का खुलासा किया। ब्रह्मपुत्र के ऊपरी मध्य हिस्से से लेकर ल्हासा के दक्षिण–पूर्व वाले हिस्से तक छह बड़े बांध बनाने की योजना है। इस श्रंष्खला के पहले बांध जांगमू का निर्माण साल 2009 में ही शुरू हो गया है। इस योजना के तहत जांगमू से आगे निचली धारा पर जियाचा, लेंगदा, झोंगदा और लैंगझेन में चार नए बांध बनाए जाएंगे। छठा बांध झांगमू से ऊपर की ओर जिएक्सू में बनाया जाएगा। यह श्रंष्खला उन एक दर्जन से छोटे बांधों के अलावा है जो चीन पहले ही ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों जैसे यामद्रोक सो, पैगड्डुओ, निगत्री पायी और ड्रिकांग पर बना चुका है। चीन की सबसे गंभीर योजना ब्रह्मपुत्र के जल को बड़े पैमाने पर ग्रेट बेंड से मोड़कर उत्तर की ओर भेजने की है। ग्रेट बेंड वह जगह है जहां से ब्रह्मपुत्र अचानक तेजी से मुड़ती हुई भारत की ओर जाती है। इस मोड़ की वजह से एक ऐसे दर्रे का निर्माण होता है जो अमेरिका के ग्रैंड कैनयॉन से भी बड़ा है। इस क्षेत्र में जिस तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है उससे साफ संकेत मिलता है कि यहां जलधारा को मोड़ने और बिजली उत्पादन का काम किया जा रहा है।

वास्तव में चीन के एक नए सरकारी ग्रिड मैप से पता चलता है कि ग्रेट बेंड को जल्दी ही चीन के बिजली आपूर्ति वाले अन्य हिस्सों से जोड़ दिया जाएगा। यह इस बात का साफ संकेत है कि चीन वहां पर विशालकाय बांध बनाने का काम शुरू कर चुका है। इस योजना का समर्थन चीन के सरकारी जलविद्युत उद्योग के नेता झांग बोटिंग ने भी किया है जो चीन जलविद्युत इंजीनियरिंग सोसाइटी के उप महासचिव हैं।

तिब्बत में अपने विशालकाय परियोजनाओं के बलबूते अब वास्तव में चीन इतना ताकतवर हो चुका है कि जल को भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल युद्ध के दौरान खुलेआम या शांति के समय चुपके से किया जा सकता है।

अपने नदी तट के प्रभुत्व को इस्तेमाल करने को चीन कष्तसंकल्प है, इससे तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लेने का भारत का आत्मघाती निर्णय उजागर हो चुका है। जैसे की सीमा के मामले में बार–बार भारत रक्षात्मक रुख अपनाता रहा है वैसे ही जल के मामले में भी भारत चीन के बांध परियोजनाओं के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रहा है। तिब्बत और चल रही परियोजनाओं को चीन का आंतरिक मामला स्वीकार कर लेना एक ऐसी गलती साबित हुआ है जिसकी आगे चलकर भारत को बड़ी कीमत चुकानी होगी। हालांकि, यदि कोई साहसी, दूरदृष्टा नेतृत्व हो तो वह देर किए बिना पिछली गलतियों को सुधार भी सकता है।

(लेखक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में प्रोफेसर हैं)

अपने नदी तट के प्रभुत्व को इस्तेमाल करने को चीन कष्तसंकल्प है, इससे तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लेने का भारत का आत्मघाती निर्णय उजागर हो चुका है। जैसे की सीमा के मामले में बार–बार भारत रक्षात्मक रुख अपनाता रहा है वैसे ही जल के मामले में भी भारत चीन के बांध परियोजनाओं के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रहा है।